# राजस्थान फ्लैगशिप योजनाएं 2025

## 25 फ्लैगशिप योजनाएं

## सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण

GK Search Engine

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित 25 बड़ी योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया है।

- मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन के बाद आयोजन विभाग की ओर से 11 अप्रैल को इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
- बता दें कि इसमें खास बात यह है कि इस बार फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है।
- पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी राज्य सरकार द्वारा संचालित 33 योजनाओं को फ्लैगशिप का दर्जा दिया था।

GK Search Engine

राज्य सरकार अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को फ्लैगशिप का दर्जा देती है। इसमें जिन योजनाओं को फ्लैगशिप घोषित किया जाता है,

उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है और हर महीने रिव्यू मीटिंग होती है। इन योजनाओं की मॉनिटरिंग रिपोर्ट हर महीने की सात तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय और आयोजन विभाग को भेजी जानी है।

# इन योजनाओं को मिला फ्लैगशिप का दर्जा

## 1. एनएफएसए में नए परिवारों को शामिल करना

- एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) में नए परिवारों को शामिल करने की प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है।
- इसके लिए, राज्य सरकारें पात्र परिवारों की पहचान करती हैं और उन्हें एनएफएसए के तहत राशन कार्ड जारी करती हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें अयोग्य लाभार्थियों को हटाया जाता है और नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जाता है.

GK Search Engine

## 2. कुसुम योजना में घटक ए, बी और सी

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना मार्च 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी
- राजस्थान में कुसुम योजना के तीन घटक हैं: घटक A, घटक B और घटक C. घटक A में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना शामिल है, जिसका लक्ष्य कुल 10 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना है. घटक B में 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप स्थापित करना शामिल है. घटक C में 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना शामिल है.
- वित्तीय सहायता: बैंक के अनुसार किसानों को पंप की लागत का 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जाती है,

GK Search Engine

## 3. संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (विद्युत आपूर्ति ढांचे को मजबूत करने के लिए)

- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना:
- भारत सरकार ने पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्काम्स को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्काम्स को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को मंजूरी दी है।
- इस योजना का 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 में 3,03,758 करोड़ रुपये का परिव्यय है

GK Search Engine

## 4. लाडो प्रोत्साहन योजना (गरीब परिवार में बालिका के जन्म पर एक लाख रुपये का बॉन्ड)

- लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 21 साल की आयु तक कुल 1.5 लाख रुपए की राशि 7 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी.
- इस योजना के तहत शुरुआत की 6 किस्तें लड़की के माता-पिता या अभिभावकों के बैंक खाते में जमा होंगी, जबकि अंतिम और 7वीं किस्त लड़की के स्वयं के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
- पहले यह योजना 'राजश्री योजना' के नाम से जानी जाती थी, जिसे दिसंबर में बदलकर 'लाडो प्रोत्साहन योजना' कर दिया गया

GK Search Engine

## 5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना और सिंचाई के तहत खेती योग्य भूमि का विस्तार करना है. इसका मुख्य लक्ष्य हर खेत को पानी उपलब्ध कराना और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है.

राजस्थान में इस योजना को 2015-16 से लागू किया जा रहा है और राज्य सरकार विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान कर रही है.

GK Search Engine

## 6. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए)

- आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितम्बर, 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है।
- इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है

## 7. कर्मभूमि से मात्र भूमि अभियान (वाटर हारवेस्टिंग)

- वर्षाजल सहेजने की परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया "कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका निभाने जा रहा है।
- शुभारंभ अक्टूबर 2024
- इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाने जा रही है।
- शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं और जयपुर जिलों में कार्य प्रारम्भ किए गए हैं

GK Search Engine

## 8. स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] 2 अक्टूबर, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत उप-मिशनों में से एक है।

**स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम): चरण II (2019-2025)**

ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के बाद, संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के उद्देश्य से एसबीएम-जी चरण II का शुभारंभ किया गया, अर्थात 2024-25 तक ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना और सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल में बदलना।

## 9. स्वामित्व योजना (सर्वे कर परिवारों को पट्टे बांटना)

- 24 अप्रैल, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देना है।
- भूमि सीमांकन के लिए उन्नत ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करते हुए, यह योजना संपत्ति मुद्रीकरण को बढ़ावा देती है, बैंक ऋण तक पहुँच को आसान बनाती है, संपत्ति विवादों को कम करती है और व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना को बढ़ावा देती है
- स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख परिवारों को भूमि पट्टे वितरित किये जाएंगे।

GK Search Engine

## 10. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना

- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 27 जनवरी 2016 से इसी सोच के साथ की गई थी कि बारिश का जल गांव से बहने के बजाय गांवों के निवासियों, जानवरों और खेतों में काम आए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांवों को वर्षा के जल की हर बूंद को बचाकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (नगरीय) का द्वितीय चरण 20 जनवरी, 2018 से शुरू हुआ था, जिसमें राज्य के सभी 191 शहर शामिल थे.

## 11. अटल ज्ञान केंद्र (तीन हजार से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण)

- प्रदेश में साढ़े 11 हजार ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे।
- प्रत्येक ज्ञान केंद्र पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने यह घोषणा की।

## 12. मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान

- माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 29 मार्च को राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत कोटा में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया। यह अभियान प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक परिदृश्य को सुदृढ बनाएगा
- विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
- साथ ही पठन दक्षता के आकलन व उपचार के लिए एआई आधारित एप, विद्यार्थी उपस्थिति एप, डिजिटल प्रवेशोत्सव एप व राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के ऑन डिमांड परीक्षा एप का भी शुभारम्भ किया।

GK Search Engine

## 13. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई थी.
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना और सभी मौसम में सड़कों का निर्माण करना है, खासकर उन इलाकों में जहां 500 (मैदानी क्षेत्रों में) या 250 (पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में) से अधिक आबादी वाले गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं.
- 100% केन्द्र प्रायोजित योजना

## 14. अटल प्रगति पथ

- राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाने की घोषणा की
- उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 206.35 करोड़ की लागत के 52 अटल प्रगति पथों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।
- ग्राम पंचायतों में अटल पथ बनने से ग्रामीणों को जाम व जलभराव सहित अन्य समस्याओं से भी पूरी तरह निजात मिल सकेगी। योजना के तहत सड़कों की चौड़ाई सात मीटर तक होने की वजह से पहले अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। अटल पथों के नेटवर्क की वजह से इलाके के गांव-ढाणियों के लोगों को फायदा मिल सकेगा।

GK Search Engine

## 15. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

- प्रारंभ  25 जून 2015
- 1 सितंबर 2024 से पाँच वर्षों तक
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) एक सरकारी योजना है जो शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए है। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है. योजना में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति और समाज के अन्य वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

GK Search Engine

## 16. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

- स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को आरम्भ किया गया
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी (SBM-U) 2.0
- योजना प्रारम्भ : अक्टूबर, 2021
- अवधि तक मान्य : 31 Mar 2026
- वित्त पोषित :
- राज्य सरकार : 40%
- केन्द्रीय सरकार : 60%
- स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण व ठोस कचरा प्रबन्धन किया जाता है

GK Search Engine

## 17. मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना

- मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का हुआ शुभारंभ:- 16 दिसम्बर
- इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल दिया जाएगा।
- इस योजना में लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80 हजार तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

## 18. पीएम विश्वकर्मा योजना

- 17 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'पीएम विश्वकर्मा योजना' का शुभारंभ किया।
- योजना में ज़िला स्तर पर बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाता है। आवश्यकतानुरूप इन्हें प्रशिक्षण मिलता है
- प्रशिक्षण में हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड
- हर लाभार्थी को 15 हज़ार रुपए टूल-किट के लिये दिये जाएंगे।

GK Search Engine

## 19. मिशन हरियालो राजस्थान

- हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई।
- राज्य के मुख्यमंत्री ने दूदू ज़िले के गाहोता में एक पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया।
- 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से प्रेरित होकर, राज्य सरकार ने 'मिशन हरियालो राजस्थान' के तहत अगले पाँच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए।
- राजस्थान सरकार ने "हरियालो राजस्थान अभियान" के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

GK Search Engine

## 20. जल जीवन मिशन

- केंद्रीय बजट 2025-26 में शेष (20%) ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (JJM) की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
- जल जीवन मिशन (JJM):
- जल जीवन मिशन: JJM को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना है।
- इस योजना के तहत, राजस्थान में साल 2024 तक 92.84 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था

GK Search Engine

## 21अमृत योजना

- अमृत योजना (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) 25 जून, 2015 को शुरू हुई थी. यह योजना 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी.
- अमृत योजना 2.0 एक भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य शहरों को आत्मनिर्भर और जल-सुरक्षित बनाना है. यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी और यह 5 साल के लिए है.
- अमृत योजना 2.0 में राजस्थान के 176 शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है.
- 2025 में, राजस्थान में अमृत योजना के तहत 5,123 करोड़ रुपये की लागत से 183 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति परियोजनाएं संचालित की जाएंगी. अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत, 5,830 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से जल आपूर्ति परियोजनाओं पर चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाएगा.

GK Search Engine

## 22. पंच गौरव योजना

- राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर  दिसम्बर 2024 में राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में 'पंच-गौरव' कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत हर जिले में एक-एक उपज, वानस्पतिक प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल एवं खेल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- पंच गौरव योजना के तहत 550 करोड़ रुपये के कार्य करवाने का प्रस्ताव

## 23. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत सामान्य ग्रामीण इलाकों में ₹1,20,000 और दुर्गम इलाकों (पहाड़ी क्षेत्रों) में ₹1,30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तथा PMAY-G के तहत बनने वाले मकानों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें शौचालय की व्यवस्था भी शामिल है।

GK Search Engine

## 24. पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना

- यह योजना पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू की गई है
- राजस्थान में BPL परिवारों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के तहत गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की कवायद शुरू की है।
- राज्य में लगभग 22 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं
- योजना के पहले चरण में कम बीपीएल परिवारों वाले 5 हजार गांवों को लागू किया जाएगा
- इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- BPL परिवारों पर खर्च होंगें एक एक लाख रूपए

GK Search Engine

## 25. नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी

- नमो ड्रोन दीदी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करती है। यह योजना कृषि क्षेत्र में महिलाओं को अधिक योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।
- महिलाओं को सौर पैनल खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का कार्यक्रम गरीबी कम करने के साथ ही ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने
- राजस्थान में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अगले 5 सालों में हर साल 3 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- राजस्थान में "बैंक सखी" एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को बैंक की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त बनाना है.

GK Search Engine

GK Search Engine